इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये

(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 3 अंक सं. : 09 अप्रैल 2011

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

भारतीय रिज़र्व बैंक--1
मुख्य घटनाएं-- 1
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां---2
बैंकिंग जगत की घटनाएं---2
विनियामकों के कथन --3
विदेशी मुद्रा विनिमय--4
सूक्ष्मवित्त -- --4
अर्थव्यवस्था--4
बीमा--5
पूंजी बाज़ार---5
नयी नियुक्तियां---5
उत्पाद एवं गंठजोड---6
अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक---6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं -- 7
शब्दावली ---7
आईआईबीएफ की गतिविधियां--7
संस्थान समाचार---8
बाज़ार की खबरें---8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

भारतीय रिज़र्व बैंक की मध्य-तिमाही की समीक्षा - 17 मार्च 2011

मौद्रिक उपाय

वर्तमान स्थूल-आर्थिक आकलन के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित उपाय करने का निर्णय लिया है :

चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत पुनर्खरीद (रेपो) दर को 25 आधार अंक बढ़ा कर 6.5 प्रतिशत से 6.75 प्रतिशत करने

चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत प्रत्यावर्ती पुनर्खरीद दर को तात्कालिक प्रभाव से 25 आधार अंक बढ़ा कर 5.5 प्रतिशत से 5.75 प्रतिशत करने।

चलनिधि

चलनिधि समायोजन सुविधा के माध्यम से निवल चलनिधि निषेचन मुख्यत: सरकारी खर्चों में वृद्धि और उसके परिणामस्वरूप रिज़र्व बैंक के पास सरकार की नकद शेषराशियों में आई गिरावट के कारण जनवरी में लगभग 93,000 करोड़ रुपये के औसत से घट कर फरवरी 2011 में 79,000 करोड़ रुपये तथा मार्च में (16 मार्च तक) और घट कर 68,000 करोड़ रह गया। इसके अलावा, चलनिधि की समग्र स्थिति के रिज़र्व बैंक की सहूलियत के स्तर (बैंकों की निवल मांग एवं सावधि देयताओं के +/- 1 प्रतिशत) के निकट पहुंचने की आशा है, यद्यपि अग्रिम कर वसूली के कारण मार्च के उत्तरार्ध में इसके कुछ हद तक अस्थायी दबाव में आने की संभावना है।

मुख्य घटनाएं

एटीएम लेनदेनों के लिए पहचान का दूसरा विवरण शीघ्र ही

कार्ड से सम्बन्धित धोखाधड़ियों को रोकने में सहायता करने की मुहिम के तहत बैंक ग्राहकों को शीघ्र ही एटीएम और डेबिट कार्ड से सम्बन्धित लेनदेनों के लिए पहचान के दूसरे विवरण का उपयोग करना होगा। वर्तमान में एटीएम से सम्बन्धित लेनदेन के लिए ग्राहक केवल स्थायी पहचान संख्या (पिन) का उपयोग करते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री जी. गोपालकृष्णन का कहना है कि गतिशील संख्याएं सृजित की जा सकती हैं तथा एटीएमों में ऐसी गतिशील संख्याएं सृजित करने की व्यवस्था की जा सकती है।

किराना दुकानों में एटीएम

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को किराना दुकानों में प्रचलन के आधार पर बिक्री केन्द्र (POS) कही जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक खुदरा मशीनें लगाने की अनुमति प्रदान कर दी है। यह सुविधा दुकान में ही डेबिट कार्ड से एक बार में 1,000 रुपये तक के नकदी आहरण की अनुमति देगी। कम से कम पांच बैंकों - यथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीबीआई बैंक और ऐक्सिस बैंक ने चुनिंदा शहरों में व्यापारी प्रतिष्ठानों में इन इलेक्ट्रॉनिक खुदरा मशीनों अथवा बिक्री केन्द्र में नकदी मशीनों को स्थापित करना आरंभ कर दिया है। नेटवर्क का विस्तार होने तथा अन्य बैंकों के इसमें शामिल हो जाने पर इसे शीघ्र ही अखिल भारतीय आधार वाली सेवा बन जाना चाहिए।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

चेक समाशोधन प्रणाली का सितम्वर तक पूर्णत: कम्प्यूटरीकरण

गैर-माइकर समाशोधन गृहों के कम्प्यूटरीकरण सहित चेक समाशोधन से सम्बन्धित कार्य के कम्प्यूटरीकरण की बैंकों से उठने वाली मांग को पूरी करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक नयी एक्सप्रेस चेक समाशोधन प्रणाली (ECCS) कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। यह पैकेज इमेज इन्फोसिस्टम्स नामक एक बाह्य विक्रेता के माध्यम से विकसित किया गया है तथा अब परिनियोजन के लिए तैयार है। एक्सप्रेस चेक समाशोधन प्रणाली (ECCS) का कार्यान्वयन (roll-out) अप्रैल और सितम्बर के बीच पूरा कर लिया जाएगा।

मौद्रिक दृष्टिकोण का संकेत देने के लिए केवल पुनर्खरीद दर का उपयोग

भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री दीपक मोहन्ती की अध्यक्षता वाली एक समिति ने यह सिफारिश की है कि भारतीय रिज़र्व बैंक को उन बहुविध उपायों को समाप्त कर देना चाहिए, जिनका

उपयोग वह मौद्रिक नीति से सम्बन्धित दृष्टिकोण का संकेत देने के लिए करता है तथा जैसा कि विकसित बाज़ारों के शीर्ष बैंक करते हैं एकमात्र पुनर्खरीद दर को अपनाए रहना चाहिए। इसके अलावा, समिति ने विचार व्यक्त किया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक को उस वर्तमान तदर्थ चलनिधि सुविधा , जिसके माध्यम से वह असाधारण चलनिधि दबावों से निपटता है, के स्थान पर एक स्थायी बट्टा दर के रूप में निष्क्रिय बैंक दर को पुनर्जीवित करना चाहिए। इस नयी सुविधा को अपवादात्मक स्थायी सुविधा (ESF) कहा जा सकता है, जिसके अधीन बैंक उनके द्वारा अनिवार्य सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR), जो इस समय 24% है, के तहत धारित बॉण्डों के एक प्रतिशत अंश को गिरवी रख कर उधार ले सकते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों पर शिकंजा कसा

भारतीय रिज़र्व बैंक इस भय के वशीभूतं कि बैंकों के मामले में कठोर विनियमन से कारबार के मुड़ कर गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के पास चले जाने के कारण विनियामक अंतरपणन से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहन बढ़ गए हैं, गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों पर विनियामक दिशानिर्देशों को और कठोर बना सकता है। शीर्ष बैंक द्वारा गैर-बैंकिंग कम्पनियों पर पूंजी बाज़ार में निवेश करने तथा सहायक कम्पनियों का गठन करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का प्रतिबंध न लगाए जाने से निर्मित होने वाले विनियामक अंतरों को भी मिटाए जाने की संभावना है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि इन कम्पनियों को मार्च, 2012 के अंत से मौजूदा 12% के बजाय 15% का अपेक्षाकृत अधिक पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखना होगा।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

अभिनव पहचान पर आधारित वित्तीय समावेशन मॉडेल का परीक्षण शुरू

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने अपने "आधार" (अभिनव पहचान संख्या - यूआईडी) पर आधारित वित्तीय समावेशन लेनदेन मॉडेल का झारखंड में क्षेत्र परीक्षण आरंभ कर दिया है। यह मॉडेल ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहकों को अभिनव पहचान अधिप्रमाणन का उपयोग करते हुए किसी भी बैंक के कारबार संपर्कियों (BCs) के साथ बैंकिंग लेनदेन करने में समर्थ बनाता है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (AEPS) कही जाने वाली उक्त पहलकदमी की शुरूआत भारतीय अभिनव पहचान प्राधिकरण, बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास एवं अनुसंधान संस्थान, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिल कर की गई है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री ए.पी. होता का कहना है कि "ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहक किसी भी बैंक के कारबार संपर्की के साथ शेषराशि की जानकारी, नकदी आहरण, नकदी जमा तथा किसी अन्य आधार ग्राहक को निधि अंतरण करने जैसे मूलभूत बैंकिंग लेनदेन करने में समर्थ होंगे। यह शेषराशि की जानकारी अथवा धनराशि आहरित करने हेतु किसी भी बैंक के एटीएम का उपयोग करने की सुविधा की ही भांति है।"

अप्रैल -जनवरी वाली अवधि में इंडिया इंक ने बाह्य वाणिज्यिक उधार के माध्यम से 23% अधिक निधियां जुटाईं

प्रचुर अपतटीय चलनिधि नें इंडिया इंक की इस वित्तीय वर्ष के पहले 10 महीनों में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ECBs) के माध्यम से 23% अधिक निधियां जुटाने में सहायता की है। अप्रैल 2010 से जनवरी 2011 की अवधि में भारतीय कम्पनियों ने बाह्य वाणिज्यिक उधारों के माध्यम से (अप्रैल 2009 से जनवरी 2010 तक की अवधि में 15.154 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में) 18.703 बिलियन अमरीकी डालर जुटाए। जनवरी 2011 में भारतीय कम्पनियों ने (जनवरी 2010 में 1.319 बिलियन अमरीकी डालर के मुकाबले) 2.709 बिलियन अमरीकी डालर जुटाए।

अधिक मांग के कारण जमा प्रमाण पत्रों के निर्गम में बढ़ोत्तरी

वर्षांत में जमाराशियों में वृद्धि दर्शाने की आपाधापी में बैंक आक्रामक रूप से जमा प्रमाण पत्र (CDs) जारी कर रहे हैं, जिससे इनकी मात्रा एक दिन में 8,000 करोड़ रुपये के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। इस आशय की अटकलें लगाई जा रही हैं कि मार्च महीने में यह मात्रा बढ़ कर 1 करोड़ रुपये तक हो सकती है। बैंकों ने फरवरी में लगभग 70,000-80,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

1 वर्षीय खजाना बिल, जमा प्रमाण पत्र के बीच क्रय-विक्रय अंतर बढ़े

बैंकों द्वारा सांविधिक चलनिधि अनुपात को बनाए रखने की उनकी अपेक्षा के मद्देनज़र खजाना बिलों की मांग को देखते हुए बैंकों के जमाराशियां जुटाने हेतु छीना-झपटी करने के परिणामस्वरूप 1 वर्षीय खजाना बिलों और उतनी ही परिपक्वता अवधि वाले जमा प्रमाण पत्रों की दरों में क्रय-विक्रय अंतर लगभग 80 आधार अंकों (bps) के सामान्य अंतर के समक्ष 250 आधार अंक बढ़ गए। केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड के नियत आय के प्रधान श्री रितेश जैंन यह मत व्यक्त करते हैं कि "खजाना बिलों और जमा प्रमाण पत्रों के बीच यह असंतुलन बैंकों द्वारा आस्ति-देयता असंतुलन निधीयन अंतर को सहूलियत के स्तर से अधिक बढ़ने का अवसर दिए जाने के कारण है। हालांकि, यह निवेशकों को अपनी धनराशि को दो अंकों वाली मीयादी जमा दरों में अवरुद्ध करने का अनूठा अवसर प्रदान करता है।"

अल्पावधि कारपोरेट ऋणों की कोई पूछ नहीं

चलनिधि संकुचन के कारण अल्पावधि कारपोरेट ऋणों की मांग घटती जा रही है और प्रतिफल में ब□ोत्तरी हो रही है। इसके अलावा, निवेशक भी (बैंकों से) उपलब्ध आकर्षक प्रतिफल और संतुलित ऋण गुणवत्ता वाले ऋण पत्रों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। 3 माह से 1 वर्ष तक की अवधि वाले कारपोरेट ऋण के कीमत-लागत अंतर (spread) में 50-75 आधार अंकों की वृद्धि हो गई है। ऋण

का कीमत-लागत अंतर सरकारी और कारपोरेट ऋण पत्रों के प्रतिफलों के बीच प्रतिफल से सम्बन्धित अंतर होता है। कारपोरेट ऋण खंड में खरीदी-बेची गई मात्रा 4 मार्च, 2011 को समाप्त सप्ताह में राष्ट्रीय शेयर बाज़ार (NSE) में 703.90 करोड़ रुपये से घट कर 484.21 करोड़ रुपये रह गई।

5 वर्षों में 80% परिवारों को बैंकिंग नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा : भारतीय उद्योग परिसंघ

भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) द्वारा बोस्टन कन्सल्टैंसी ग्रुप के परामर्श से किए गए एक अध्ययन में यह कहा गया है कि सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया वित्तीय समावेशन अभियान आगामी पांच वर्षों में 47% के मौजूदा स्तर से 80% परिवारों को औपचारक बैंकिंग नेटवर्क से जोड़ देगा। इसके फलस्वरूप वित्तीय सेवा-प्रदाता पांचवे वर्ष तक 3,500 करोड़ रुपये के इस अप्रयुक्त लाभकारी अवसर से लाभ उठाने में सफल होंगे।

बैंकर सूक्ष्मवित्त ऋणदाताओं को प्राथमिकताप्राप्त दर्जा देने के पक्ष में

बैंकरों ने कुछेक सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (MFIs) के वैयक्तिक आचरण पर ध्यान दिए बिना सूक्ष्मवित्त क्षेत्र को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की हैसियत जारी रखने के पक्ष में राय व्यक्त की है। इसके अलावा, वे बैंकिंग और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं, दोनों ही के लिए केवल एक ही विनियामक के पक्ष में हैं। इसके अतिरिक्त बैंकरों ने भारतीय रिज़र्व बैंक से सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा उनके उधारदाताओं को ऋण समय पर न चुकाए जाने पर बैंकों को दंडित न किए जाने के लिए भी कहा है, क्योंकि बैंक सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को कोई भी ऋण देने से पहले कर्तव्यपरायणता का पालन करते हैं। भारतीय बैंक संघ (IBA) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री के. रामकृष्णन का तर्क है कि उक्त क्षेत्र की प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र वाली हैसियत कुछेक सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा कदाचरण के कुछेक कार्यों के कारण वापस नहीं ली जानी चाहिए।

वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए बैंकों को सहायक कम्पनियों का मार्ग आजमाना चाहिए

बोस्टन कन्सल्टैंसी ग्रुप के एशिया-पैसिफिक के अध्यक्ष डॉ. जन्मेजय सिन्हा के अनुसार भारतीय बैंकों को उनके वित्तीय समावेशन अभियान में लागतों में कमी लाने के लिए सहायक कम्पनियों के मार्ग को आजमाना चाहिए। इस बात को देखते हुए कि बैंकों की प्रति कर्मचारी 5.5 लाख की औसत वितरण लागत निषेधात्मक है, डॉ. सिन्हा का कहना है कि उन्हें मानव संसाधन लागत में कमी लाने के लिए सहायक कम्पनियां प्रवर्तित करने पर विचार करना चाहिए। ये सहायक कम्पनियां बैंकिंग सुविधा रहित ग्रामीण एवं कस्बाई क्षेत्रों में मूलभूत बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए स्थानीय प्रतिभाओं का (प्रति कर्मचारी 1 लाख रुपये या उससे कम की पर्याप्त रूप से निम्न लागत पर) उपयोग कर सकती हैं।

विनियामक अंतरपणन पर भारतीय रिज़र्व बैंक की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए बोस्टन कन्सल्टैंसी ग्रुप के प्रमुख ने यह सुझाव दिया है कि नीति-निर्माताओं को केवल वित्तीय समावेशन अभियान के लिए सहायक कम्पनियों के गठन की अनुमति देनी चाहिए।

विनियामकों के कथन

सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के विनियमन अप्रैल से लागू हो सकते हैं

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव ने कहा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के विनियमन पर मालेगाम समिति के - उधार दरों पर पर सीमा सहित कुछेक प्रस्तावों को यथासंभव शीघ्रतापूर्वक अप्रैल 2011 से कार्यान्वित करना आरंभ कर सकता है। अक्तूबर 2010 में श्री वाई. एच. मालेगाम की अध्यक्षता में गठित उक्त समिति सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के भीतर ही गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी - सूक्ष्म वित्त संस्था के रूप में गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की एक श्रेणी के सृजन की सिफारिश की थी, जिसे राज्य साहूकारी अधिनियम से छूट प्राप्त होगी।

अनर्जक आस्तियों पर बेहतर निगरानी रखने में सहायता के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का कम्प्यूटरीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के. सी. चक्रवर्ती ने कहा है कि कोर बैंकिंग समाधान (CBS) पूरा हो जाने पर केन्द्रीय बैंक बैंकों की अनर्जक आस्तियों पर निगरानी रखने हेतु बेहतर स्थिति में होगा। डॉ. चक्रवर्ती ने यह मत व्यक्त किया है कि "किसी शारीरिक (मैनुअल) हस्तक्षेप के बिना उद्गम स्थल से आने वाले आंकड़ों से डाटा की विश्वसनीयता और अखंडता बढ़ेगी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक शाखाओं के आंकड़ों में पर्याप्त विसंगतियों का पता लगाया है।" उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि बैंक शाखाओं को पालियों में विभाजित करके उनके कामकाज का समय बढ़ाए जाने से न केवल शाखाओं के कार्यात्मक बोझ में कमी आएगी, अपितु यह उपाय बैंकों की प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग द्वारा लेनदेन लागत को कम करने में भी सहायता करेगा। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि "लेनदेन लागतों में कमी आ जाने पर बैंक जमाराशियों पर अधिक ब्याज प्रदान कर सकते हैं तथा उधार राशियों पर कम ब्याज दर लगा सकते हैं। अधिक से अधिक लोगों द्वारा प्रौद्योगिकी का उपयोग करना आरंभ कर दिए जाने पर उसकी लागत में कमी हो जाती है।"

इर्डा वृद्धावस्था के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध कराएगा

यूनिट-सम्बद्ध पेंशन योजनाओं में निवेश करने वालों को अब अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इर्डा) भिन्न-भिन्न गारंटियों वाली चार-पांच प्रकार की पेंशन योजनाएं आरंभ करने की योजना बना रहा है। वर्तमान में उपलब्ध योजना परिपक्वता पर 4.5% के

प्रतिलाभ की गारंटी देती है। केवल चंद कम्पनियां ही यह योजना उपलब्ध कराती हैं, क्योंकि गारंटी उनके लिए इक्विटी में निवेश करना कठिन बना देती है। 4.5% का प्रतिलाभ निवेशकों को आकर्षक नहीं लगता। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यूनिट-सम्बद्ध पेंशन योजनाओं से सम्बन्धित दिशानिर्देशों को संशोधित कर रहा है तथा वह आश्वस्त लाभों वाले, किन्तु आवश्यक रूप से प्रतिलाभ दर वाले नहीं, अधिक उत्पाद तैयार करने के लिए प्रयासरत है।

बासेल दिशानिर्देशों को कार्यान्वित करना चुनौतीपूर्ण सिद्ध होगा

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव ने यह आह्वान किया है कि भारतीय बैंकों को कार्यकुशलता बढ़ाने की दिशा में कार्य करना होगा। "पिछले 15-20 वर्षों में भारतीय बैंकिंग में प्रभावशाली वृद्धि हुई है। हालांकि, कार्यकुशलता में सुधार लाना भारतीय बैंकों के लिए एक बड़ी चुनौती रही है, क्योंकि आपको बचते निवेशों में संग्रहीत करनी होंगी, जिसके लिए आपको अपेक्षाकृत अधिक ब्याज दर देनी होती है। बैंकों के लिए निवल ब्याज मार्जिनों में कमी लाना आवश्यक है। उन्हें बासेल-III मानदंडों को भी कार्यान्वित करना आवश्यक है, क्योंकि बैंकिंग की लागतों में शीघ्र ही बढ़ोत्तरी होने वाली है" यह कहना है डॉ. सुब्बाराव का, यद्यपि वे चेतावनी देते हैं कि "बासेल-III को परिचालित करना एक बौद्धिक चुनौती बनने वाली है। आपको यह पहचान करने की आवश्यकता होगी कि आप किस समय झुकाव वाले बिन्दु पर हैं। यदि आप इसमें गलती करते हैं, तो आप स्वयं अपने बैंक के भविष्य को ही संकट में डाल देंगे।"

बैंकों को बाज़ार से धन जुटाना चाहिए

डॉ. के. सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार बैंकों के लिए उनके तुलन पत्रों को बढ़ाने हेतु उनकी अतिरिक्त पूंजी के लिए सरकार पर निर्भर करने के बजाय बाज़ार से पूंजी जुटाने की आवश्यकता है, क्योंकि बासेल-III करार के प्रवृत्त हो जाने पर उन्हें पर्याप्त रूप से पूंजीकृत रखना एक चुनौती सिद्ध होगा।

विदेशी मुद्रा विनिमय

अप्रैल 2011 माह की विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) / अनिवासी विदेशी जमाराशियों की न्यूनतम दरें

अनिवासी विदेशी जमाराशियों की लिबोर / अदला-बदली (swap) दरें					
मुद्रा	लिबोर	अदला-बदली (swap)			
	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष		
अमरीकी डालर	0.78250	0.9560	1.4970		

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की लिबोर / अदला-बदली दरें

	लिबोर	अदला-बदली			
मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.78250	0.956	1.497	1.980	2.398
जीबीपी	1.59875	1.8590	2.3060	2.6620	2.9570
यूरो	1.94750	2.355	2.666	2.897	3.074
जापानी येन	0.56875	0.400	0.453	0.530	0.633
कनाडाई डालर	1.90083	1.954	2.315	2.623	2.869
आस्ट्रेलियाई डालर	5.55000	5.190	5.310	5.580	5.680

स्रोत : भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (FEDAI)

विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियां

मद	**18 मार्च 2011 के दिन**	**18 मार्च 2011 के दिन**
	करोड़ रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
1	**2**	**3**
कुल प्रारक्षित निधियां	13, 68, 708	303, 506
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	12, 34, 236	273,727
ख) सोना	1, 00, 041	22, 143
ग) विशेष आहरण अधिकार	23,577	5, 229
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	10, 854	2,407

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

विदेशी मुद्रा श्रेणी-निर्धारण में भारत ऊंचे पायदान पर

उभरते विदेशी मुद्रा बाज़ारों पर मेकलाई फाइनैन्सियल द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह दर्शाया गया है कि जहां भारतीय बाज़ार वर्ष 2010 में उसके समग्र श्रेणी-निर्धारण की दृष्टि से ऊपर उठ कर दूसरे स्थान पर पहुंच गया, वहीं उसका बाज़ार परिपक्वता सूचकांक (MMI) अन्य बाज़ारों द्वारा दर्शाई गई 12% की औसत गिरावट की तुलना में 21% कम हो गया। वर्ष 2010 में बाज़ार परिपक्वता सूचकांक (MMI) की दृष्टि से (14 में से) शीर्ष 3 बाज़ार थे रूस, भारत और दक्षिण अफ्रीका। भारत को छोड़कर, जो ऊंचे उठ कर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, इन तीनों ही बाज़ारों को वर्ष 2007 में यह सम्मान प्राप्त हुआ था।

सूक्ष्मवित्त

बैंकों ने सूक्ष्न वित्त संस्थाओं से कमजोर संपार्श्वकों को आस्तियों से बदलने के लिए कहा

कुछेक सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के ऋण संविभाग की गुणवत्ता में आई गिरावट के फलस्वरूप बैंकों ने सूक्ष्म वित्त संस्थाओं से जोखिमों से बचाव व्यवस्था करने हेतु कमजोर संपार्श्विकों को बेहतर गुणवत्ता वाली आस्तियों से प्रतिस्थापित करने के लिए कहा है। यह मुद्दा विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश में ऋण संविभाग से प्रासंगिक है। एक सूक्ष्म वित्त संस्था के कार्यपालक का कहना है कि गैर-बैंकिंग कम्पनियों को उधार देते समय बैंक प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में बुक किए गए व्यवसाय (अधारकर्ताओं को ऋण) की मांग करते हैं। आश्रय विकल्प के रूप में ग्राहकों को दिए गए ऋण ही एकमात्र आस्ति होते हैं।

आन्ध्र प्रदेश ने सूक्ष्म वित्त संस्था अधिनियम के प्रसार क्षेत्र को और व्यापक बनाया

सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा आन्ध्र प्रदेश सूक्ष्मवित्त (साहूकारी) विनियमन अधिनियम को वापस लिए जाने की मांग किए जाने के बावजूद राज्य सरकार ने उसके प्रसार क्षेत्र को और व्यापक कर दिया है। इस आधार पर कि यह स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के केवल महिला सदस्यों पर ही लागू होगा, कुछेक सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा किए गए छूट से सम्बन्धित दावों पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने यह कहा है कि इस अधिनियम के प्रावधान स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के परिवार के पुरुषों को दिए गए ऋणों पर भी लागू होंगे।

अर्थव्यवस्था

राजकोषीय घाटे में कमी मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखेगी : बैंकर

बैंकरों द्वारा बजट का हार्दिक स्वागत किया गया है, जिनकी राय यह है कि घाटे में कमी के बाद ब्याज दरों और मुद्रास्फीति में कमी होगी। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय साख श्रेणी निर्धारण एजेन्सी स्टैंडर्ड एण्ड पुअर की साख श्रेणी निर्धारण सेवा यह अनुभव करती है कि आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने तथा राजकोषीय समेकन प्राप्त करने का प्रयास करने वाली सरकार द्वारा एक चुनौतीपूर्ण वर्ष का सामना किए जाने की संभावना है। वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने कुल व्यय को सीमित रख कर मुद्रास्फीति को रोकने की मंशा व्यक्त की है। बजट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की पीड़ा को कम करने के लिए सामाजिक व्ययों को भी बढ़ा दिया है।

वित्तीय कम्पनियां उभरते बाज़ारों में जोखिमों का पुनराकलन करेंगी

डन एण्ड ब्रैडस्ट्रीट की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय क्षेत्र के महारथी अर्थात् बैंकों, बीमा कम्पनियों और व्यवसायों द्वारा, विशेषत: पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में बढ़ते राजनीतिक विक्षोभ की पृष्ठभूमि में उभरते बाज़ारों में निहित राजनीतिक जोखिमों का पुनराकलन एवं मूल्य-पुनर्निर्धारण किए जाने की संभावना है। ट्यूनीशिया, इजिप्ट और लीबिया में व्याप्त विक्षोभ की पृष्ठभूमि में ऋण एवं बीमा लागतों के न केवल मेना (मध्य-पूर्व और उत्तरी अफ्रीका) में, अपितु अन्य अस्थिर और तानाशाही वाले देशों में भी बढ़ने की आशा है।

पोर्टफोलियो निवेशों से सम्बन्धित अस्थिर पूंजी प्रवाहों में बढ़ोत्तरी

देश की विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि में अस्थिर पूंजी प्रवाह (जिसमें संचयी पोर्टफोलियो अंतर्वाहों और अल्पावधिक ऋण का समावेश है) अनुपात मार्च 2010 के अंत में 58.1% के मुकाबले सितम्बर 2010 के अंत में बढ़कर 68.1% हो गया। यह वृद्धि पोर्टफोलियो निवेशों में अप्रैल - सितम्बर 2010 की अवधि मे (पिछले वर्ष की इसी अवधि के 17.9 बिलियन डालर की वृद्धि की तुलना में) 23.8% बढ़ोत्तरी के कारण हुई।

डॉ. डी. सुब्बाराव, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऋण प्रवाह की अपेक्षा विदेशी इक्विटी जैसे ऋणेतर प्रवाहों के प्रति भारत की वरीयता और उसके साथ ही साथ विदेशी संस्थागत निवेश (FII) जैसे अल्पावधिक प्रवाहों की अपेक्षा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) जैसे दीर्घावधिक प्रवाहों के प्रति वरीयता पर बल दिया था। अस्थिर पूंजी प्रवाहों के प्रति भारतीय रिज़र्व बैंक की चिंता को रेखांकित करते हुए डॉ. सुब्बाराव कहते हैं कि "उभरते बाज़ार वाली अर्थव्यवस्थाओं को उनकी निवेश सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए पूंजी प्रवाहों की निश्चित रूप से जरूरत होती है। किन्तु उन्हें वे जितनी अवशोषित कर सकती हैं उससे अधिक अंतर्वाह प्राप्त होने पर उसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था वित्तीय और आर्थिक, दोनों ही दृष्टियों से प्रभावित होती है। अतिरक्त प्रवाहों से निपटने का कोई सरल तरीका नहीं है। जो बात समस्या को प्रचंड बना देती है वह यह है कि ये प्रवाह अचानक रोधनों एवं विपर्ययों के प्रति प्रवण होते हैं, अर्थात् वे अचानक विपरीत दिशा की ओर मुड़ सकते हैं और किसी अर्थव्यवस्था से बाहर जा सकते हैं, इस प्रकार वे वित्तीय स्थिरता के लिए गंभीर खांच निर्मित कर सकते हैं।"

बीमा

मीलें आपके मोटर बीमा प्रीमियम का निर्धारण करेंगी

'कम चलाएं कम चुकाएं' शीघ्र ही भारत की कम से कम तीन मोटर बीमा कम्पनियों का बिक्री बिन्दु बनने जा रहा है। बजाज एलाएंज, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और भारती अक्स जनरल इंश्योरेंस इटली में लोकप्रिय तथाकथित पे ऐज यू ड्राइव पॉलिसियों के रूपांतरण को आधार बना कर एक पॉलिसी तैयार कर रहे हैं। यह बीमा योजना आपको ड्राइव किए गए मीलों के अनुसार प्रीमियम का भुगतान करने की सुविधा प्रदान करती है। आपकी मोटरबीमा पॉलिसी के नवीकरण के लिए आने पर मील जितने कम होंगे, प्रीमियम भी उतने ही कम होंगे। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने पहले ही एक ऐसी प्रायोगिक परियोजना आरंभ कर रखी है, जिसमें उसने वाहनों के सेट पर एक अन्वेषक उपकरण संस्थापित कर रखा है जो मालिक-□लित और वाणिज्यिक उपकरण का मिश्रण है। ये उपकरण इस समय पारगत दूरी, प्रयुक्त सड़क की स्थिति, ड्राइविंग के समय - यथा दिन या रात जैसे आंकड़ों का पता लगा रहे हैं।

पूंजी बाज़ार

बॉण्ड बाज़ारो में विदेशी संस्थागत निवेश मार्च में 800 मिलियन डालर के स्तर पर

बॉण्ड बाज़ारों में विदेशी अंतर्वाह मार्च में पहले कुछेक व्यापार सत्रों में ही लगभग 800मिलियन डालर के स्तर तक पहुंच गए हैं। फरवरी में विदेशी निवेशक रुपये में मूल्यवर्गित ऋण के निवल विक्रेता थे। अब उनके द्वारा स्वाधिकृत संचित रकम 20 मिलियन डालर से अधिक हो गई है। यह तत्काल नहीं स्पष्ट हो पाया कि विदेशी निवेशकों ने जिल्टें खरीदी हैं या कारपोरेट बॉण्ड या फिर दोनों मिलाकर। बेंचमार्क (जिल्ट) बॉण्डों पर प्रतिफल इस बजटीय घोषणा के बाद से घट गया है कि वर्ष 2011-12 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.6% तक नियंत्रित रखा जाएगा। मई 2020 में परिपक्व होने वाली 7.8% वाली प्रतिभूति पर प्रतिफल 28 फरवरी 2011 से तीन आधार अंक घट कर 7.98% हो गया है।

सेबी ने 91 दिवसीय खजाना बिलों के सम्बन्ध में वायदा संविदाओं की शुरूआत की अनुमति दी

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 91 दिवसीय खजाना बिलों (T-Bills) के सम्बन्ध में वायदा संविदाओं की तात्कालिक प्रभाव से शरूआत किए जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। इस लिखत का क्रय-विक्रय शेयर बाज़ारों के मुद्रा व्युत्पन्नी खण्ड में किया जाएगा। शेयर बाज़ारों को इन संविदाओं की शुरूआत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से अनुमति मिलने के बाद करने की सलाह दी गई है। संविदा का न्यूनतम आकार 2 लाख रुपये होगा तथा उसे प्रात: 9 बजे से 5 बजे सायं तक खरीदा-बेचा जा सकेगा। इस संविदा को 100 में से 5% का वायदा बट्टा प्रतिफल घटाकर उद्धृत किया जाएगा, भाव (quote) 100 - 5 = 95 होगा। वायदा बट्टा प्रतिफल में कोई परिवर्तन मुद्रा की दृष्टि से 5 रुपये के बराबर होगा। इस संविदा की अधिकतम अवधि 12 माह होगी,

जिसमें तीन मासिक संविदाएं (निकटवर्ती अगली और दूरवर्ती माहों) और उसके बाद मार्च जून सितम्बर और दिसम्बर की परिपक्वताओं वाली तीन तिमाही संविदाओं का समावेश होगा।

सरकार ने यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता प्राप्त शेयर बाज़ार के रूप में अधिसूचित किया

मुद्रा व्युत्पन्नियों के लिए भारत के अधुनातन शेयर बाज़ार यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज को सरकार द्वारा एक ऐसे मान्यता प्राप्त शेयर बाज़ार के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है, जिसमें क्रय-विक्रय को सट्टेबाजी वाला लेनदेन नहीं माना जाएगा। यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज ने 20 सितम्बर 2010 को मुद्रा व्युत्पन्नियों की तथा 29 अक्तूबर को मुद्रा विकल्प की शुरूआत की थी।

नयी नियुक्तियां

भारतीय रिज़र्व बैंक के नये कार्यपालक निदेशक

श्री आर. गांधी ने भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री गांधी प्रशासन और कार्मिक प्रबन्धन (राजभाषा सहित) बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, मानव संसाधन विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का दायित्व संभालेंगे।

भारतीय बैंक संघ के प्रमुख

श्री एम. डी. मल्या, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने श्री ओ. पी. भट्ट की भारतीय स्टे्ट बैंक के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्ति के बाद भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। श्री ओ. पी. भट्ट 31 मार्च, 2011 को अपनी सेवानिवृत्ति तक भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष और इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स के सभापति भी थे।

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के प्रबन्ध निदेशक

श्री शिव कुमार ने स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (SBBJ) के प्रबन्ध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इसके पूर्व वे मुख्य महा प्रबन्धक के रूप में भारतीय स्टेट बैंक हैदराबाद सर्किल के प्रधान थे।

केनरा बैंक में नये कार्यपालक निदेशक

श्रीमती अर्चना भार्गव ने केनरा बैंक की नयी कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उक्त कार्यभार संभालने के पूर्व श्रीमती भार्गव पंजाब नैशनल बैंक में महा प्रबन्धक थीं।

उत्पाद एवं गंठजोड़

संगठन	जिस संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ है	उद्देश्य
इंडियन ओवरसीज बैंक	एमएक्स (अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कारपोरेशन	उसके अवनमित क्रेडिट कार्ड व्यवसाय को सहारा देने के लिए। इंडियन ओवरसीज बैंक ने सह-ब्रॉण्डयुक्त क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कारपोरेशन के साथ गंठजोड़ किया है।
पंजाब नैशनल बैंक	भारतीय सेना	पीएनबी रक्षक सैन्यबल वेतन पैकेज को बढ़ावा देने के लिए
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	नोकिया	भारतभर में नोकिया द्वारा समर्थित 'यूनियन बैंक मनी. प्रवर्तित। यह सेवा मध्यवर्तियों की आवश्यकता को समाप्त करते हुए तथा सुविधा प्रदान करते हुए उपभोक्ताओं को उनके मोबाइल उोकरणों का उपयोग करते हुए अन्य व्यक्तियों को धन अंतरित करने, कारबार संपर्कियों, कैश-आउट केन्द्रों (पंजीकृत नोकिया भण्डारों) एवं एटीएमों से नकदी आहरित करने तथा उपयोगिता बिलों का भुतान करने के साथ ही साथ प्रदत्त सिम कार्डों (टॉप-अपों) को रिचार्ज करने में समर्थ बनाएगी।
कर्नाटका बैंक	बारट्रॉनिक्स	दूर-दराज़ के गावों में बैंकिंग सेवाओं की शीघ्र वदयवस्था करने के लिए। अपनी वित्तीय समावेशन योजना के तहत बैंक 80 गांवों में 2.3 लाख से अधिक हिताधिकारियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की योजना बना रहा है। इनमें 43 को 31 मार्च, 2011 तक और शेष को 31 मार्च, 2012 तक यह सेवा उपलब्ध करा दी जाएगी।

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (BIS)

पिछले अंक से जारी

1988 में समिति ने सामान्य रूप से बासेल पूंजी करार कही जाने वाली पूंजी मापन प्रणाली की शुरूआत करने का निर्णय लिया। इस प्रणाली में वर्ष 1992 के अंत तक 8% के न्यूनतम पूंजी मानक सहित एक ऋण जोखिम मापन ढांचे के कार्यान्वयन की व्यवस्था की गई थी। 1988 से इस ढांचे को न केवल सदस्य देशों में, अपितु अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय बैंकों वाले लगभग सभी अन्य देशों में भी क्रमिक रूप से लागू किया गया है। जून 1999 में समिति ने संशोधित पूंजी पर्याप्तता ढांचे

के लिए एक प्रस्ताव जारी किया। प्रस्तावित पूंजी □ांचे में तीन स्तंभों : न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं, जिसमें 1988 वाले करार में नियत किए गए मानकीकृत नियमों को परिष्कृत किए जाने का प्रस्ताव है; किसी संस्था की आंतरिक मूल्यांकन प्रक्रिया और पूंजी पर्याप्तता के पर्यवेक्षी पुनरीक्षण; तथा पर्यवेक्षी प्रयासों की अनुपूरक व्यवस्था के रूप में बाज़ार अनुशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रकटन के प्रभावी उपयोग का समावेश था। ऐसे बैंकों, उद्योग समूहों तथा पर्यवेक्षी प्राधिकारियों, जो समिति के सदस्य नहीं हैं, से अन्योन्य क्रिया (संवाद) करने के बाद उक्त संशोधित ढांचा 26 जून 2004 को जारी किया गया। यह पाठ राष्ट्रीय नियम-निर्माण तथा बैंकों के लिए नये ढांचे के कार्यान्वयन के लिए अपनी तैयारियों को पूरी कर लेने के आधार का काम करता है।

पिछले कुछेक वर्षों में समिति ने पूरे विश्व में सुदृढ़ पर्यवेक्षी मानकों को बढ़ावा देने की दिशा में अधिक आक्रामक ढंग से कदम बढ़ाए हैं। कई एक ऐसे अधिकार क्षेत्रों, जो समिति के सदस्य नहीं है, के घनिष्ठ सहयोग से इसने 1997 में "प्रभावी बैंकिंग पर्यवेक्षण के मुख्य सिद्धांतों" का एक सेट तैयार किया, जिसमें पर्यवेक्षी प्रणाली की व्यापक रूपरेखा उपलब्ध कराई गई है। इसके कार्यान्वयन एवं मूल्यांकन को सुगम बनाने के लिए समिति ने अक्तूबर 1999 में "मुख्य सिद्धांतों की कार्यप्रणाली" तैयार की। इन मुख्य सिद्धांतों और कार्यप्रणाली को संशोधित किया गया तथा अक्तूबर 2006 में जारी किया गया।

देशों के एक व्यापक समूह को बासेल में आगे बढ़ाए जा रहे कार्यों से जुड़ने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से समिति ने हमेशा अपने सदस्यों और अन्य बैंकिंग पर्यवेक्षी प्राधिकरणों के बीच संपर्क एवं सहयोग को प्रोत्साहित किया है। यह विश्वभर के पर्यवेक्षकों को प्रकाशित एवं अप्रकाशित दस्तावेज़ परिचालित करती है। कई एक मामलों में सदस्येतर देशों के पर्यवेक्षी प्राधिकरणों को अपने आप को समिति की पहलकदमियों से जोड़ने के लिए सार्वजनिक तौर पर अनुकूल होते पाया गया है। इन संपर्कों को बैंकिंग पर्यवेक्षकों के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों (ICBS), जो प्रत्येक दो वर्ष पर आयोजित किए जाते हैं, के माध्यम से और सुदृढ़ बनाया गया है। बैंकिंग पर्यवेक्षकों का पिछला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन वर्ष 2010 के शरदकाल में सिंगापुर में आयोजित किया गया था।

समिति के सचिवालय की व्यवस्था बासेल में स्थित अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक द्वारा की गई है। पन्द्रह व्यक्तियों वाले सा□ालय में कार्यरत कर्मचारी सदस्य संस्थाओं से मुख्यत: व्यावसायिक पर्यवेक्षकों की प्रतिनियुक्ति के माध्यम से जुटाए गए हैं। समिति और उसकी कई एक विशेषज्ञ समितियों के लिए सचिवालयीन कार्य का निर्वाह करने के अलावा वह सभी देशों के पर्यवेक्षी प्राधिकरणों को सलाह देने हेतु सदैव तत्पर रहता है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

मुख्य दर वाली अवधि (Key Rate Duration)

अन्य सभी परिपक्वता अवधियों को स्थिर रखते हुए यह निश्चित परिपक्वता के प्रतिफल में 1% के परिवर्तन पर किसी प्रतिभूति की संवेदनशीलता अथवा पोर्टफोलियो के मूल्य को मापती है :

$$\text{मुख्य अवधि} = \frac{\text{पी - पी +}}{2 \text{ X1\% X पी}_{\text{ओ}}}$$

जिसमें

पी = प्रतिफल में 1% की कमी के बाद प्रतिभूति का मूल्य

पी + = प्रतिफल में 1% की वृद्धि के बाद प्रतिभूति का मूल्य

पी ओ = प्रतिभूति का मौलिक मूल्य

खजाना हाजिर दर वक्र के साथ 11 परिपक्वताएं होती हैं और प्रत्येक की मुख्य दर वाली अवधि की गणना की जाती है। पोर्टफोलियो प्रतिफल वक्र के साथ मुख्य दर वाली अवधियों का योग पोर्टफोलियो की प्रभावी दर के बराबर होता है।

शब्दावली

आस्ति-देयता असंतुलन

बैंकों की निधियों का मूल स्रोत जमाराशियां होती हैं, जो विशिष्ट रूप से अल्प से मध्यम अवधि की परिपक्वता अवधियों वाली होती हैं। उनका 3-5 वर्षों में निवेशकों को वापस भुगतान किया जाना आवश्यक होता है। इसके विपरीत बैंक आम तौर पर उधारकर्ताओं को अपेक्षाकृत लम्बी अवधियों के लिए ऋण देते हैं। उदाहरण के लिए गृह ऋणों की अवधि 20 वर्षों तक की हो सकती है। अधिक अल्प परिपक्वता अवधियों वाली निधियों से इस प्रकार के दीर्घावधिक ऋण दिए जाने को आस्ति-देयता असंतुलन कहा जाता है।

आईआईबीएफ की गतिविधियां

ग्राहक सेवा और बैंकिंग संहिताओं एवं मानकों में प्रमाण पत्र परीक्षा

एक सेवा उद्योग होने के कारण बैंकिंग को उसके ग्राहकों को दी जाने वाली सेवा की गुणवत्ता को उसकी प्राथमिकताओं में शीर्ष क्रम पर रखना होता है। बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में ग्राहकों की अपेक्षाएं हमारे देश के विभिन्न स्थानों एवं भौगोलिक केन्द्रों में भिन्न-भिन्न होती हैं। बदलते समय के साथ ग्राहक सेवा की गुणवत्ता के बारे में सभी स्तरों पर अपेक्षाओं में पिछले 3-4 दशकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने तथा बैंक कर्मचारियों द्वारा गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान किए जाने के उद्देश्य से संस्थान ने भारतीय बैंकिंग संहिता एवं मानक बोर्ड (BCSBI) के सहयोग से ग्राहक सेवा में एक प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम की शुरूआत की है। उक्त पाठ्यक्रम का उद्घाटन 12 नवम्बर, 2010 को भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के. सी. चक्रवर्ती द्वारा किया गया तथा पहली परीक्षा 30 जनवरी 2011 को आयोजित की गई।

वेबेक्स कक्षाएं

संस्थान ने हाल ही में सिस्को (CISCO) सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ उनके वेबेक्स नामक उत्पाद के माध्यम से वेब समर्थित कक्षाओं की व्यवस्था करने हेतु एक करार किया है। इस सुविधा के तहत संस्थान सम्बन्धित क्षेत्र के ऐसे विषय-विशेषज्ञों, जो हमारे संसाधन व्यक्तित्व के रूप में कार्य करते रहे हैं, द्वारा दिए गए व्याख्यानों की वीडियो- रिकार्डिंग की गई सामग्री उपलब्ध कराएगा । रिकार्ड की गई इस सामग्री तक पहुंच की सुविधा ऐसे सभी अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी, जिन्होंने जेआईआईबी और सीएआईआईबी परीक्षाओं के लिए पंजीकरण करा रखा हो। अभ्यर्थीगण इन सामग्रियों को अपनी सुविधा के अनुसार तथा उनकी पसंदगी वाले स्थान पर प्राप्त कर सकते हैं। यह व्यवस्था प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा निजी शिक्षक रखे जाने जैसी ही है, बशर्ते उसके पास नेट सुविधा सहित कम्प्यूटर मौजूद हो। इस सुविधा को ऐसे सभी अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराए जाने की आशा है, जिन्होंने मई / जून 2011 की परीक्षा हेतु पंजीकरण कराया है। वेबेक्स कक्षाओं के तैयार हो जाने पर इसकी अलग से घोषणा की जाएगी।

- भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास संख्या : 69228 / 98 के अधीन पंजीकृत
पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / दक्षिण -42 / 2010 -12
पूर्व-अदायगी के बिना प्रेषित करने का लाइसेंस संख्या एमआर/ तक/ डब्ल्यूपीपी-15 /
दक्षिण / 2010 - 12 मुंबई
- मुंबई पत्रिका चैनल छंटाई कार्यालय मुंबई - 1 पर प्रत्येक महीने की 25वीं और 28वीं तारीख को प्रेषित करें।

संस्थान समाचार

केन्या में 11वां मानव संसाधन सम्मेलन

संस्थान 28 अप्रैल से 1 मई 2011 तक नैरोबी, केन्या में "वृद्धि की प्राप्ति के लिए रूपांतरण का प्रबन्धन" विषय पर 11 वें बैंक मानव संसाधन प्रबन्धन सम्मेलन का आयोजन करेगा।

परियोजना वित्त में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम

संस्थान आईएफएमआर, चेन्नै के सहयोग से परियोजना वित्त में 14वें प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम का आयोजन कर रहा है। बैच के लिए कैम्पस प्रशिक्षण 2 मई से 7 मई 2011 तक आयोजित होगा।

अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

बाज़ार की खबरें

भारित औसत मांग दरें

8.00
7.50
7.00
6.50
6.00
5.50
01/03/11 03/03/11 05/03/11 09/03/11 10/03/11 12/03/11 14/03/11
16/03/11 17/03/11 18/03/11 19/03/11 21/03/11 25/03/11

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, मार्च 2011

- मांग मुद्रा बाज़ार श्रेणीबद्ध रहे।
- पहले सप्ताह में चलनिधि की स्थिति सहज रही।
- वित्त वर्ष के अंतिम सप्ताह में मांग दरों में बढ़ोत्तरी हुई।
- दरें 6.39 और 7.66 के बीच मंडराती रहीं।

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

80
75

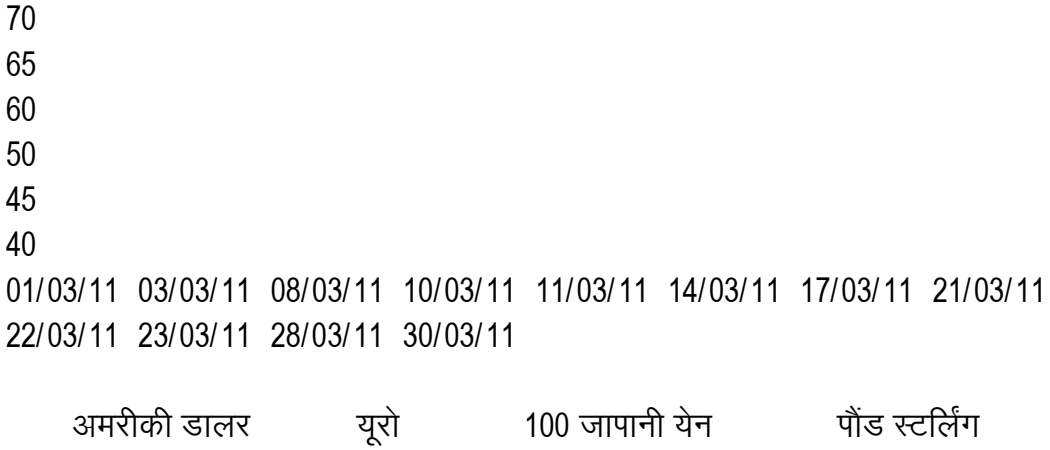

स्त्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

- 3 मार्च को अस्थिर व्यापार सत्र के बाद रुपया अपेक्षाकृत कमजोर 44.945 / 955 के समक्ष 45.0359 / 0450 पर बंद हुआ, क्योंकि तेल से सम्बन्धित डालर की मांग के परिणामस्वरूप क्षुब्ध इक्विटी बाज़ार के उत्साह में मंदी आ गई।
- 7 मार्च को भारतीय मुद्रा प्रति डालर 45.04 / 45.05 पर बंद हुई, जो शुक्रवार को कारबार के अंत में 44.98 / 99 से 0.1% कमजोर रही।
- शुक्रवार, अर्थात् 18 को घटनाओं के घालमेल के बीच रुपये का मूल्य बढ़ कर 45.13 हो गया।
- 28 को इस अनुमान के आधार पर कि स्थानीय आयातक तिमाही के अंत वाले बिलों का निपटान करने हेतु विदेशी मुद्रा की खरीद बढ़ाएंगे, सात दिनों में रुपया पहली बार कमजोर पड़ा। सोमवार के लेनदेन में रुपया 0.4% लुढ़क कर प्रति डालर 44.84 पर आ गया।
- बुधवार के लेनदेन में रुपये का मूल्य 0.1% बढ़ कर प्रति डालर 44.75 हो गया। रुपया तिमाही में 0.1% की अपनी गिरावट से अलग हो कर इस माह में 1.1% बढ़ा।
- माह के दौरान यूरो के मूल्य में 1.12% की गिरावट आई, जबकि स्टर्लिंग के मूल्य में 2.36% की वृद्धि हुई।

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

01/03/11 07/03/11 09/03/11 11/03/11 14/03/11 15/03/11 16/03/11 17/03/11 18/03/11 24/03/11 25/03/11 28/03/11

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

श्री आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, श्री आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, 'दि आर्केड', विश्व व्यापार केन्द्र, 2री मंजिल, पूर्व स्कंध, कफ परेड, मुंबई - 400 005 से प्रकाशित।

संपादक : श्री आर. भास्करन

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
दि आर्केड, विश्व व्यापार केन्द्र, 2री मंजिल, पूर्व स्कंध, कफ परेड,
मुंबई - 400 005
टेलीफोन : 2218 7003 / 04 / 05 फैक्स : 91-22-2218 5147 / 2215 5093
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न अप्रैल, 2011